दुनिया की सबसे मंहगी जारवा झोपड़ी

(संवाददाता द्वारा)

पोर्ट ब्लेयर, 29 अक्टूबर

जारवा आदिम जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए भारत सरकार की ओर से प्रतिवर्ष करोड़ों का बजट भेजा जाता है। परन्तु उस बजट का सही इस्तेमाल हो भी पाता है यह हमेशा। विवाद का मुद्दा रहा है। जारवाओं के सम्बंध में आयोजित संगोष्ठी एवं विचार गोष्ठी में इस पर बहस हो चुकी है, परन्तु आज तक स्थानिय प्रशासन इस पर सही स्पष्टीकरण दे नहीं पाया है। जारवाओं के भोजन के नाम पर केले, नारियल का जिक्र से अधिक प्रशासन की आदिम जनजाति समिति के कर्मचारियों के वेतन, वाहनों एवं अन्य फिजूल खर्चों का बार–बार उल्लेख किया जाता रहा। यहाँ तक आदिवासी स्वास्थ्य के नाम एक नए बजद का खेल शुरू हो चुका है। इन्ही सभी मामलों को लेकर पिछली सरकार के दौरान उस समय के सांसद श्री विष्णु पद रे ने तो लोक सभा में प्रति वर्ष प्रति जारवा पर एक लाख रुपए के बजट खर्च किए जाने पर सवाल उठा कर अच्छा–खाशा हंगामा खड़ा कर दिया था।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

दुनिया की सबसे मंहगी...

परन्तु इसके बाद भी प्रशासन ने इस मामले को न केवल सरकार को बल्कि देश की जनता को पाषण युग कालिन इस आदिम जनजाति के मामले में अंधेरे में रखा है।

अभी हाल ही में 'सुबह तक' के एक दल को कदमतला के यात्रा के दौरान जारवाओं के मामले में कई चौंकाने वाले तथ्यों का पता चल पाया है। कदमतला उप स्वास्थ्य केन्द्र के छोटे से अस्पताल के परिसर में स्थित एक छोटे से आकार वाले झोपड़ी नुमा जारवा वार्ड का निर्माण पिछले कुछ वर्षों में किया गया था। इस बारे में बतलाया जाता है कि झोपड़ी के निर्माण पर पांच लाख से अधिक बजट आया है। अगर इस बारे में जरा भी सच्चाई है तो इससे पता चल जाता है कि जारवाओं के मामले में कितने बड़े पैमाने में लूट–खसोट मची हुई है। जारवा ओं के इलाकों में आदिम जनजाति कल्याण समिति का अपना काला सम्राज्य है। उप राज्यपाल प्रो. राम कापसे ने एक राष्ट्रीय स्तर की जारवाओं के मामले के सम्बंध में आयोजित गोष्ठी में इस समिति के पुर्नगठन में दिए गए आश्वासन के बाद भी आज तक कुछ नहीं हो पाया।

अंक में)